भारत की संसद भाग 2

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है।
- भारत के समेकित कोष पर अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का शुल्क लिया जाता है।
- स्पीकर के आचरण पर एक व्यापक प्रस्ताव को छोड़कर चर्चा नहीं की जा सकती है

अध्यक्ष या उपसभापति, सदन के जीवन के दौरान आम तौर पर पद धारण करते हैं, लेकिन उनका कार्यालय निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पहले समाप्त हो सकता है:

- उनके द्वारा सदन का सदस्य बनना बंद कर दिया।
- लिखित में इस्तीफे से, उपाध्यक्ष को संबोधित किया और इसके विपरीत।
- सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाकर (अनुच्छेद 94)
- अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संकल्प को स्थानांतरित करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो.

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष / उपाध्यक्ष	
1st **अध्यक्ष**:	गणेश वासुदेव (जी.वी.) मावलंकर
1st **अध्यक्ष (जनजातीय)**	पी.ए संगमा
1st **अध्यक्ष (महिला)**	मीरा कुमार
1st **उपाध्यक्ष**	एम. अनंतशयनम अय्यंगारे

- जबकि उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन है, अध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और वोटों की समानता के मामले को छोड़कर वोट कर सकते हैं (अनुच्छेद 96)
- सदन की अन्य बैठकों में अध्यक्ष पहली बार मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन वोटों की समानता के मामले में एक वोट डाल सकता है।
- लोकसभा के भीतर आदेश को बनाए रखने और उसके नियमों की व्याख्या करने के लिए अध्यक्ष के पास अंतिम शक्ति होती है.
- कोरम की अनुपस्थिति में अध्यक्ष सदन को स्थगित कर देता है या बैठक को स्थगित कर देता है जब तक कि कोई कोरम न हो।
- प्रक्रिया को विनियमित करने या सदन में व्यवस्था बनाए रखने के स्पीकर के आचरण पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है (अनुच्छेद 122).

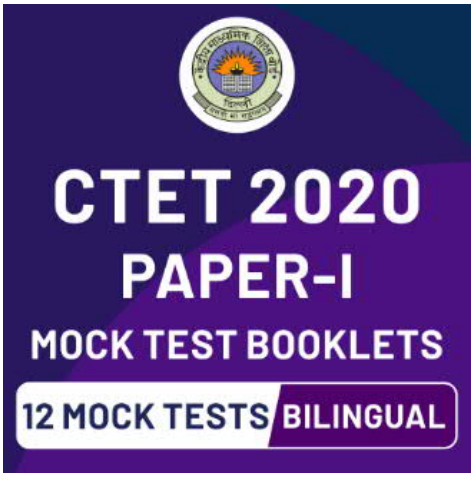

- स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है (अनुच्छेद 118(4)).
- जब एक धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में प्रेषित किया जाता है, तो अध्यक्ष यह प्रमाणित कर सकता है कि यह धन विधेयक है (अनुच्छेद 110 (4))
- एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है।
- जबकि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या अध्यक्ष सदन के बैठक से अनुपस्थित रहता है, उपसभापति की अध्यक्षता होती है, सिवाय इसके कि जब स्वयं हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो

राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जब तक कि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है।
- जब अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का प्रदर्शन उप सभापति द्वारा किया जाता है।
- अध्यक्ष को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।
- राज्य सभा में अध्यक्ष की शक्तियाँ लोकसभा में अध्यक्ष के समान हैं, सिवाय इसके कि अध्यक्ष के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जैसे धन विधेयक को प्रमाणित करना या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना.

राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष: डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
प्रथम उपाध्यक्ष: एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
प्रथम उपाध्यक्ष (महिला): श्रीमती वायलेट अल्वा

संसद के विशेषाधिकार

प्रत्येक सदन के विशेषाधिकारों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

1. जिनका सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आनंद लिया जाता है।
2. जो संसद के प्रत्येक सदन से संबंधित हैं, एक सामूहिक निकाय के रूप में.

सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार इस प्रकार हैं: सदन या समिति की बैठक की निरंतरता के दौरान गिरफ्तारी से स्वतंत्रता एक सदस्य को छूट देती है, जिसके वह सदस्य और या बैठे होते हैं.

- यह प्रतिरक्षा नागरिक मामलों में गिरफ्तार करने या आपराधिक मामलों में या निवारक निरोध के कानून के तहत सीमित है।
- संसद सत्र के दौरान एक गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए सदन की छुट्टी के बिना एक सदस्य को नहीं बुलाया जा सकता है.

प्रत्येक सदन की दीवारों के भीतर बोलने की स्वतंत्रता है.

- बोलने की स्वतंत्रता पर सीमा यह है कि संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो सकती है, न्यायाधीश के निष्कासन के प्रस्ताव के अलावा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में (अनुछेद 121).

सामूहिक रूप से सदन के विशेषाधिकार हैं:

- बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने और दूसरों द्वारा प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का अधिकार।
- दूसरों को बाहर करने का अधिकार।

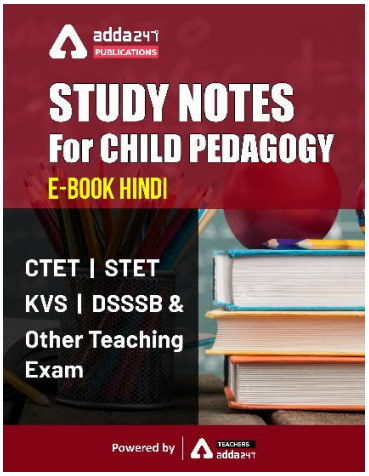

- सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार। संसदीय दुर्व्यवहार को प्रकाशित करने का अधिकार।
- इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार.

संसद में विधायी प्रक्रियाएं: धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों से संबंधित संसद में विधायी प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं::

- संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक का परिचय
- परिचय के बाद प्रेरणा
- चयन समिति द्वारा रिपोर्ट
- सदन में विधेयक का पारित होना जहां इसे पेश किया गया था
- दूसरे सदन में पारित होना
- राष्ट्रपति का आश्वासन

धन विधेयक और वित्तीय बिल: एक बिल को मनी बिल कहा जाता है, यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से निपटने के प्रावधान शामिल हैं:

- किसी भी कर का थोपना, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन
- भारत के समेकित निधि से धन की निकासी या उसकी निकासी।
- राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है।
- लोक सभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद, यह राज्य सभा को प्रेषित किया जाता है।
- राज्य सभा न तो मनी बिल के संशोधन को अस्वीकार कर सकती है।
- यह राज्य सभा की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए लोकसभा तक है।
- यदि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक वापस नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है.